एफ.सं. 96/1/2017-सीएक्स.आई

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स

दिनांक 10 मार्च, 2017

प्रति,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (सभी)
प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सेवा कर (सभी)
प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क (सभी)

मैडम सर,

विषय: कारण बताओ नोटिस, न्यायनिर्णयन और वसूली पर मास्टर परिपत्र - के संबंध में।

कारण बताओ पर निन्यानबे परिपत्रों और निर्देशों पर कृपया ध्यान आकर्षित किया जाता है

बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नोटिस और अधिनिर्णय, अनुलग्नकों में दिए गए हैं

यह मास्टर परिपत्र। ये परिपत्र व्यापार और क्षेत्रीय संरचनाओं के संदर्भों को संबोधित करते हैं और

उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करें। बोर्ड का अभ्यास करता है

इन परिपत्रों को समय-समय पर समेकित करना ताकि स्पष्टता और संदर्भ में आसानी सुनिश्चित की जा सके।

कारण बताओ नोटिस, न्यायनिर्णयन कार्यवाही और के विषय पर यह मास्टर परिपत्र

वसूली प्रासंगिक कानूनी और वैधानिक प्रावधानों, अतीत के परिपत्रों को संकलित करने का एक प्रयास है

और उन परिपत्रों को रद्द करने के लिए जो प्रासंगिकता खो चुके हैं। परिपत्र के अनुबंध-I में की सूची दी गई है

उन अस्सी नौ परिपत्रों को रद्द कर दिया गया है। अनुबंध-II में सूचीबद्ध तीन परिपत्रों में नहीं है

रद्द कर दिया गया है क्योंकि उनके पास जिस विषय पर वे संबोधित करते हैं उस पर व्यापक निर्देश हैं।

2. मास्टर सर्कुलर को चार भागों में बांटा गया है। भाग I कारण बताओ नोटिस से संबंधित है

संबंधित मुद्दे, भाग II न्यायनिर्णयन कार्यवाही से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, भाग III से संबंधित है

कार्यवाही को बंद करना और शुल्क की वसूली और भाग IV विविध मुद्दों से संबंधित है।

3. मास्टर परिपत्र के प्रावधान सीबीईसी पर अधिभावी प्रभाव डालेंगे

पूरक अनुदेशों की आबकारी नियमावली उस सीमा तक जिसमें वे परस्पर विरोधी हैं।

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसके संज्ञान में लाया जा सकता है

बोर्ड की। हिंदी संस्करण का पालन करेंगे।

शंकर प्रसाद सरमा

अवर सचिव, भारत सरकार

मास्टर परिपत्र

अनुक्रमणिका:

क्र.सं.	विषय	पैरा नं।
	पार्ट-मैं	
1 मांग		1.1 -1.2
2 कारण बताओ नोटिस (एससीएन)		2.1
3	एससीएन की संरचना	2.2-2.10
4	न्यायनिर्णयन का अधिकार	2.11
5	मांग शुल्क की सीमा	3.1
6	विस्तारित अवधि	3.2 से 3.7
7	ब्याज की मांग में सीमा की प्रयोज्यता	3.8
8 विभागीय लेखा परीक्षा या सीईआरए के कारण मांग		4.1 से 4.5
9	कारण बताओ नोटिस परामर्श	5.0
10	एससीएन जारी करने का अधिकार	6.0
1 1	एससीएन में अन्यायपूर्ण संवर्धन	7.0
12 मूल्यांकन का अभ्यास बदलना		8.0
13 एससीएन की छूट		9.1 से 9.2
14	कॉल बुक मामले	9.3
	भाग द्वितीय	
15	न्यायिक निर्णय	10
16 मौद्रिक सीमाएं और अन्य मुद्दे		11.1 से 12
17	कार्यकारी आयुक्तालय का क्षेत्राधिकार	12.1
18	लेखापरीक्षा आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा निर्णय	12.2
19	डीजीसीईआई द्वारा जांचे गए मामले	12.3 से 12.5
20 कारण बताओ नोटिस की सेवा और दस्तावेजों पर भरोसा		13.0
21	निर्णय के चरण	14.1 से 14.10
22 एक न्यायनिर्णयन आदेश के लिए शुद्धिपत्र		15.0
23 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का स्थानांतरण		16.0
24 आदेश पर हस्ताक्षर		16.1
सीईआरए द्वारा उठाए गए एसओएफ/एलएआर का 25 न्यायनिर्णयन		17.1 से 17.4
	भाग III	
26 मांगों की पुष्टि		18

27 वसूली	19 से 22.4
भाग- IV	
28 निर्णयों, आदेशों, समन आदि की तामील।	23
29 डे नोवो अधिनिर्णय	24
30 स्वैच्छिक भुगतान पर कोई एससीएन नहीं	25
31 पूर्व-जमा की वापसी	26

भाग I: कारण बताओ नोटिस

1.1 मांग: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत मांग जारी की जा सकती है
जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम किया गया है
भुगतान किया गया है या जहां किसी भी कारण से कोई शुल्क गलती से वापस कर दिया गया है। कर्तव्य की मांग
लेवी के अधिकार के बिना या उससे अधिक के संग्रह शुल्क के कारण भी उत्पन्न हो सकता है
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11डी के अनुसार आरोपण कर विभाग के पास जमा नहीं किया गया।
1944.

1.2 निर्धारिती से शुल्क की मांग कारण बताओ नोटिस जारी करके की जाती है
(संक्षेप में एससीएन) कानून के प्रावधान के उल्लंघन के आरोपों को इंगित करता है जिसमें की आवश्यकता होती है
निर्धारिती को यह स्पष्ट करने के लिए कि शुल्क क्यों नहीं लगाया गया / भुगतान नहीं किया गया या कम लगाया गया / कम भुगतान किया गया
नोटिस प्राप्त करने वाले से ब्याज और जुर्माने के साथ वसूल नहीं किया जाएगा, यदि लागू हो। इसी तरह, एक शो

करदाता।

2.1 कारण बताओ नोटिस (एससीएन): कारण बताओ नोटिस (एससीएन) किसी भी कानूनी का प्रारंभिक बिंदु है
पार्टी के खिलाफ कार्यवाही यह कार्यवाही के लिए संपूर्ण रूपरेखा निर्धारित करता है जो हैं
करने का इरादा है और इसलिए इसे अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। के जारी
SCN एक वैधानिक आवश्यकता है और यह किसी भी विवाद के निपटारे के लिए मूल दस्तावेज है
कर देयता से संबंधित या प्रावधानों के उल्लंघन के लिए की जाने वाली कोई दंडात्मक कार्रवाई
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के। एक एससीएन नोटिस देने वाले को प्रदान करता है
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष अपना मौखिक या लिखित निवेदन प्रस्तुत करने का अवसर
एससीएन में लगाए गए आरोप कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य है
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आवश्यकता जिसे आमतौर पर ऑडी के रूप में जाना जाता है
अल्टरम पार्टेम जिसका अर्थ है कि किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए।

2.2 एससीएन की संरचना: एक एससीएन में आदर्श रूप से निम्नलिखित भाग शामिल होने चाहिए, हालांकि यह हो सकता है :
मामले से मामले में भिन्न:
क) मामले का परिचय

बी)। कानूनी ढांचा

सी)। तथ्यात्मक बयान और सबूतों की सराहना

डी)। चर्चा, तथ्य और कानूनी ढांचा,

इ)। सीमा पर चर्चा

एफ)। देय शुल्क और अन्य राशियों की गणना

जी)। आरोपों का विवरण

एच)। फैसला सुनाने का अधिकार।

2.3 मामले का परिचय: एससीएन के इस हिस्से में उस व्यक्ति का विवरण होना चाहिए जिसे
जिसे नोटिस जारी किया जाना है। इसमें नाम, पंजीकरण संख्या/आईईसी और . होना चाहिए
व्यक्ति का पता और जिस तरीके से उक्त व्यक्ति की पहचान बाद में की गई है
नोटिस का पाठ। कई नोटिसों को एससीएन जारी करने के मामले में, ऐसे सभी नोटिसों का विवरण
इस तथ्य के बावजूद अलग से कहा जाना चाहिए कि, व्यक्ति प्रत्येक से निकटता से संबंधित हैं
अन्य। वर्तमान कार्यवाही कैसे शुरू हुई इसकी एक बहुत ही संक्षिप्त पृष्ठभूमि पर चर्चा की जानी चाहिए
एससीएन में। उदाहरण के लिए, एक एससीएन आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा खातों की लेखापरीक्षा पर आधारित हो सकता है या
रेंज कार्यालय द्वारा वापसी की विस्तृत जांच या चोरी-रोधी आदि द्वारा खुफिया जानकारी। इस भाग में,
लेखापरीक्षा आपत्तियों/टिप्पणियों/आसूचनाओं का सार और कर्तव्य की संक्षिप्त कार्यप्रणाली
कथित अपराधी द्वारा अपनाई गई चोरी पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा, का विवरण
सत्यापन/जांच आयोजित/किया गया और सत्यापन का सारांश हो सकता है
इस भाग में भी चर्चा की जाएगी।

2.4 कानूनी ढांचा: एससीएन जारी करने वाले प्राधिकरण को कानूनी रूप से स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए
प्रावधान जिसके संबंध में व्यक्ति को नोटिस में रखा जाएगा। निर्दिष्ट करते समय
प्रावधानों, सभी प्रावधानों और कानून को सूचीबद्ध करने में बहुत सटीक होने का ध्यान रखा जाना चाहिए
जिसके संबंध में एससीएन में उल्लंघनों का आरोप लगाया जाना है।

2.5 तथ्यात्मक कथन और साक्ष्य की सराहना: एससीएन के इस भाग में, संबंधित तथ्य
के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रासंगिक चूक और कमीशन का कार्य करने के लिए
नोटिसी को सबसे उद्देश्यपूर्ण और सटीक तरीके से कहा जाना चाहिए। के रूप में सभी साक्ष्य
पूछताछ के दौरान दस्तावेजों, बयानों और भौतिक साक्ष्यों को फिर से शुरू किया गया
/जांच को क्रमानुसार इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए ताकि आरोपों को स्थापित किया जा सके
नोटिस पाने वाला। तथ्यों और सबूतों पर चर्चा करते समय, सटीक होने का ध्यान रखा जाना चाहिए और
अभिव्यक्ति में संक्षिप्त ताकि अनावश्यक विवरण से बचा जा सके।

2.6 चर्चा, तथ्य और कानूनी ढांचा: इस भाग में तथ्यों और सबूतों की आवश्यकता होती है
कारण बताओ नोटिस में निर्धारित कानूनी ढांचे के खिलाफ चर्चा की ताकि उस पर पहुंच सकें
प्रत्येक नोटिस के खिलाफ अलग-अलग चूक और कमीशन के आरोप। के आधार पर
चर्चा, आरोपों को प्रत्येक नोटिसी के खिलाफ स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप से लिखे जाने की आवश्यकता है।

2.7 सीमा पर चर्चा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार, शुल्क
जो लगाया या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान या गलत तरीके से किया गया है
वापसी की मांग केवल सामान्य अवधि के भीतर ही की जा सकती है अर्थात प्रासंगिक अवधि से दो वर्ष के भीतर
दिनांक। हालांकि, विशिष्ट मामले में, जहां उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या
धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान के कारण गलत तरीके से वापस किया गया या
तथ्यों का दमन या अधिनियम या बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन
इसके तहत शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से, तो शुल्क की मांग की जा सकती है a
प्रासंगिक तारीख से पांच साल की अवधि। SCN को स्पष्ट रूप से सामग्री का उच्चारण करना चाहिए
रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ पांच साल की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए। एक और विस्तृत
विषय पर चर्चा पैराग्राफ 3.1 से 3.6 में निहित है।

2.8 मांग की गई शुल्क की मात्रा: यह वांछनीय है कि मांग की मात्रा निर्धारित की जाए:
एससीएन, हालांकि अगर कुछ वास्तविक आधारों के कारण कम लेवी की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है:
एससीएन जारी करने के समय, एससीएन को अमान्य नहीं माना जाएगा। यह अभी भी होगा
वांछनीय है कि नोटिसी से देय राशियों की गणना के सिद्धांत और तरीके हैं
SCN के इस भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। ग्वालियर रेयन एमएफजी (डब्ल्यूवीजी) कंपनी बनाम के मामले में।
यूओआई, 1982 (010) ईएलटी 0844 (एमपी), जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुष्टि की
वही स्थिति केवल इसलिए कि शो में आवश्यक विवरण नहीं बताया गया है
कारण नोटिस, यह नोटिस को रद्द करने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह के लिए खुला है
याचिकाकर्ता को और विवरण, यदि कोई हो, जो इसके लिए कारण दिखाने के लिए आवश्यक हो सकता है, यदि
वही कमी है।

2.9 ब्याज: के प्रावधानों के तहत शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज प्रभार्य है
सीईए की धारा 11एए, 1944 या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का नियम 8 या आवश्यक परिवर्तनों सहित
सेनवैट क्रेडिट के लिए लिया गया या/और गलत तरीके से उपयोग किया गया या धनवापसी की वसूली के लिए या राशि पर
माल के खरीदार से किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर देय शुल्क से अधिक एकत्र किया गया
धाराडीडीके तहत।ꢀꢁब्याज दे यताके कसीभी उले ख कआवश्यकतानहहोसकतीहै
कारण बताओ नोटिस में क्योंकि इस संबंध में कानूनी प्रावधान स्पष्ट और निहित हैं
धारा 11ए(14)। हालांकि, एससीएन को आरोपों का एक स्व-निहित नोटिस बनाने के लिए, यह अभी भी हो सकता है
एससीएन मꢀꢁब्याज कदे यताकाउले ख करनावांछनीय होगा।

2.10 आरोपों का विवरण: इस भाग में, नोटिस के खिलाफ सभी आरोपों की एससीएन सूची की आवश्यकता है
संक्षेप किया जाना चाहिए और नोटिस पर आरोप लगाया जाना चाहिए कि कानून में प्रदान की गई कार्रवाई क्यों है,
उनके खिलाफ नहीं लिया जाना चाहिए।

2.11 न्यायनिर्णयन का अधिकार: एक एससीएन को उस प्राधिकरण का उल्लेख करना चाहिए जिसे शो का उत्तर दिया गया है
कारण नोटिस का जवाब देना आवश्यक है। माल की जब्ती के मामले में कारण बताओ का मुद्दा
माल की जब्ती का कोई भी आदेश पारित होने से पहले नोटिस अनिवार्य है। जहां एक है
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी में परिवर्तन, SCN के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया जा सकता है और उस पर तामील किया जा सकता है
नोटिसों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोटिस देने वालों के पास अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर है
उपयुक्त निर्णायक प्राधिकारी। में परिवर्तन के कारण एससीएन को शुद्धिपत्र जारी किया जाता है
अधिकार क्षेत्र, मौद्रिक सीमा, पुन: असाइनमेंट, आदि। एससीएन जारी करने वाले प्राधिकारी को
शुद्धिपत्र जारी करें और फिर फ़ाइल को नए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को स्थानांतरित करें।

3.1 मांग शुल्क की सीमा: एक कारण बताओ नोटिस जिसमें शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है
या गलत वापसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सामान्य रूप से दो साल के भीतर जारी किया जा सकता है
भुगतान न करने या शुल्क के कम भुगतान की प्रासंगिक तिथि से, जिसके बाद मांग
कालबाधित हो जाता है। जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है या किसी प्रभार्य व्यक्ति द्वारा कम भुगतान किया गया है
धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या दमन के कारण कर्तव्य के साथ
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या नियमों के किसी भी प्रावधान के तथ्य या उल्लंघन
इसके तहत शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से बनाया गया है, सीमा की लंबी अवधि लागू होती है
और संबंधित तिथि से पांच साल के भीतर ड्यूटी की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है।

3.2 विस्तारित अवधि के लिए सामग्री: विस्तारित अवधि केवल तभी लागू की जा सकती है जब
कम अवधि के मामले में विस्तारित अवधि की मांग को सही ठहराने के लिए आवश्यक सामग्री
भुगतान या कर का भुगतान न करना। यह स्थापित करने का दायित्व कि ये सामग्रियां इसमें मौजूद हैं
एक दिया गया मामला राजस्व पर है और इन सामग्रियों को शो में स्पष्ट रूप से सामने लाने की आवश्यकता है
सबूत के साथ कॉज नोटिस। कर्तव्य से बचने के इरादे का सक्रिय तत्व
विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए कार्रवाई या निष्क्रियता उपस्थित होने की आवश्यकता है।

3.3 मैसर्स कॉस्मिक डाई केमिकल बनाम सेन कलेक्टर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। उत्पाद शुल्क,
बॉम्बे [1995 (75) ईएलटी 721 (एससी) ने इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से कानून बनाया है। यह वही
संदर्भ में आसानी के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

अब जहां तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का संबंध है, यह स्पष्ट है कि अपेक्षित आशय, अर्थात,
कर्तव्य से बचने का इरादा इन्हीं शब्दों में बनाया गया है। जहाँ तक गलत बयान या का दमन
तथ्यों का संबंध है, वे शब्दों से पहले "इच्छाशक्ति" शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से योग्य हैं
"गलत बयान या तथ्यों का दमन" जिसका अर्थ है कर्तव्य से बचने के इरादे से। अगला सेट

शब्द "इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन" फिर से योग्य हैं
तुरंत निम्नलिखित शब्द "ड्यूटी के भुगतान से बचने के इरादे से"। इसलिए, यह नहीं है
यह कहना सही है कि तथ्य का दमन या गलत बयान हो सकता है, जो जानबूझकर नहीं है और
फिर भी धारा 11ए के परंतुक के प्रयोजन के लिए एक अनुमेय आधार का गठन करता है। गलत
बयान या तथ्य का दमन जानबूझकर किया जाना चाहिए।

3.4 व्याख्या के विवादित क्षेत्रों में विस्तारित अवधि: ऐसे मामले हैं जहां या तो नहीं
शुल्क लगाया जा रहा था या किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर इस विश्वास के आधार पर कम लगाया गया था कि वे
उत्पाद शुल्क योग्य नहीं थे या शुल्क की कम दर के लिए प्रभार्य थे, जैसा भी मामला हो। दोनों व्यापार
और राजस्व के क्षेत्र निर्माण इस तरह की समझ के तहत संचालित हो सकते हैं। इस प्रकार
मूल्यांकन की सामान्य प्रथा को शुल्क का भुगतान न करना या कम पर भुगतान कहा जा सकता है
दर, जैसा भी मामला हो। ऐसी स्थितियों में, बोर्ड यह स्पष्ट करते हुए परिपत्र जारी कर सकता है कि
आकलन की सामान्य प्रथा त्रुटिपूर्ण थी और क्षेत्रीय संरचनाओं को सही करने का निर्देश दे रही थी
मूल्यांकन का अभ्यास। इस तरह के परिपत्र के परिणामस्वरूप, विस्तारित के लिए मांग नोटिस जारी करना
समय की अवधि गलत होगी क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती जानबूझकर नहीं किया गया था
कर्तव्य का भुगतान।

3.5 दूसरी ओर, बोर्ड के परिपत्र हो सकते हैं जो केवल सही अभ्यास को दोहराते हैं
मूल्यांकन का जो निर्धारितियों के अनुपालन खंड द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। ऐसे में
परिस्थितियों, विस्तारित अवधि को लागू करने का निर्णय एक के तथ्यों की जांच पर निर्भर करेगा
मामला और जहां विस्तारित अवधि का आह्वान करने के लिए सामग्री मौजूद है, के लिए कारण बताओ नोटिस
विस्तारित अवधि जारी की जा सकती है। ऐसी स्थितियों में अनुपालन करने वाले वर्ग के साथ अन्याय होगा
निर्धारितियों को समय की विस्तारित अवधि का आह्वान नहीं करने के लिए, यदि सक्रिय तत्व मौजूद हैं
विस्तारित अवधि का आह्वान करें।

3.6 विस्तारित अवधि को लागू करने की शक्ति सशर्त है: विस्तारित अवधि के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति
अवधि सक्रिय अवयवों की उपस्थिति से प्रतिबंधित है जो कर्तव्य से बचने के इरादे का संकेत देते हैं:
ऊपर समझाया गया। ऐसी प्रतिबंधित शक्तियों के अंधाधुंध उपयोग से निष्फल निर्णय होते हैं,
अपील और समीक्षा, बकाया मांगों और सभी कारणों से ऊपर के आंकड़ों को बढ़ाता है
करदाताओं का अनावश्यक उत्पीड़न। इसलिए, विस्तारित अवधि को लागू करने से पहले, यह अवश्य होना चाहिए
सुनिश्चित किया जाए कि विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें मौजूद हैं।

3.7 दूसरा एससीएन विस्तारित अवधि को लागू करता है: दूसरा एससीएन जारी करना जिसमें विस्तारित अवधि का आह्वान किया गया है
पहली एससीएन लागू करने के बाद की विस्तारित अवधि को जारी करने के बाद की अवधि कानूनी रूप से नहीं है
योग्य। हालांकि, दूसरा एससीएन, यदि जारी किया जाता है, तो उसे सामग्री स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी
विस्तारित अवधि को स्वतंत्र रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ऐसे मामलों में जहां मंजूरी
निर्धारिती द्वारा आवधिक रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की जाती है, दूसरा एससीएन विस्तारित अवधि का आह्वान करता है
काफी तार्किक है जबकि के तहत की गई मंजूरी के संबंध में जानबूझकर गलत बयान के मामलों में

उपयुक्त चालान और आवधिक रिटर्न में दर्ज किया गया, दूसरा एससीएन लागू किया गया विस्तारित
अवधि को बनाए रखना मुश्किल होगा क्योंकि विभाग के पास सभी तथ्य हैं
पहले एससीएन के समय के बाद। इसलिए, भरपूर एहतियात के तौर पर यह वांछनीय है कि
पहले एससीएन के बाद विस्तारित अवधि को लागू करने के बाद, बाद के एससीएन को जारी किया जाना चाहिए
सीमा की सामान्य अवधि।

3.8 ब्याज की मांग में सीमा की प्रयोज्यता: ऐसे मामलों में जहां शुल्क और ब्याज है
मांग की गई है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 11ए में निर्धारित सीमा लागू होती है। हालाँकि, यह मई
ध्यान दें कि उन मामलों में जहां शुल्क का भुगतान देर से किया गया है और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है,
मांग की उचित प्रक्रिया के बाद ब्याज की मांग और वसूली की आवश्यकता है और
अधिनिर्णय। ऐसे मामलों में, धारा 11ए में निर्धारित सीमा की अवधि के लिए लागू होता है
ब्याज की मांग। इस संबंध में धारा 11ए(15) का उल्लेख किया जा सकता है।

4.1 विभागीय या सीईआरए (सीएजी ऑडिट) के कारण मांग: कारण बताओ नोटिस हो सकता है
आंतरिक लेखापरीक्षा या सीईआरए से उत्पन्न होने वाली लेखापरीक्षा आपत्ति के कारण जारी किया जाना आवश्यक है
सीएजी कार्यालय द्वारा किया गया। आंतरिक कारणों से कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय
लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा आयुक्त के पास है। जहां तक सीईआरए लेखापरीक्षा का संबंध है, एक विस्तृत
परिपत्र संख्या 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8.4.16 के माध्यम से परिपत्र जारी किया गया है। महत्वपूर्ण
इस संबंध में परिपत्र में निर्देश इस प्रकार हैं:
4.2 जहां विभाग गुण-दोष के आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है, वहां एक बड़ा
लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुपात। ऐसी स्थितियों में, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए
जारी करने से पहले तत्काल और जहां निर्धारिती का व्यावहारिक दृष्टिकोण प्राप्त किया जाना चाहिए
कारण बताओ नोटिस। ऐसे मामलों को कॉल-बुक में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए और होना चाहिए
मांग की पुष्टि के मामलों में जल्द से जल्द न्यायनिर्णय और राजस्व की वसूली की गई।
4.3 जहां विभाग गुणदोष के आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है, कोई कारण नहीं बतायें
मामलों में नोटिस जारी किया जाना चाहिए और विस्तृत तर्क और मामले का जवाब देते हुए जवाब दिया जाना चाहिए
विषय पर कानून। सीईआरए को जवाब देने की प्रक्रिया के अधिक विवरण के लिए, उक्त परिपत्र
रेफर किया जा सकता है।
4.4 जहां एक विवादित लेखापरीक्षा आपत्ति डीएपी बन गई है और जांच करने पर यह पाया जाता है
सीबीईसी में आयुक्त (पीएसी) या संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क) को आपत्ति होनी चाहिए
भर्ती कर लिया गया है, वे फील्ड फॉर्मेशनों को शो जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकते हैं
कारण नोटिस करें और गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करें।
4.5 यह ध्यान दिया जा सकता है कि कारण बताओ नोटिस को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है
उक्त परिपत्र के द्वारा कॉल-बुक पर कैग की आपत्ति को समाप्त कर दिया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि
उपरोक्त पैरा 4.2 से पैरा 4.4 में केवल शो जारी करने के संबंध में निर्देशों का सार दिया गया है

कारण सूचना और अधिक जानकारी के लिए उक्त परिपत्र दिनांक 8.4.2016 को देखें।

सीईआरए की आपत्तियों के कारण जारी कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया है:

परिपत्र दिनांक 8.4.2016 (ibid) में निहित है और पैरा 18.1 से . तक पुन: प्रस्तुत किया गया है

संदर्भ में आसानी के लिए इस परिपत्र का 18.4।

5.0 कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले नोटिस देने वाले के साथ परामर्श: बोर्ड ने किया है

पूर्व प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा पूर्व कारण बताओ नोटिस परामर्श

रुपये से अधिक शुल्क की मांग वाले मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करना। 50 लाख (को छोड़कर)

निवारक/अपराध संबंधी एससीएन) अनिवार्य रूप से एफ नं.

1080/09/DLA/MISC/15 दिनांक 21 दिसंबर 2015। इस तरह के परामर्श द्वारा किया जाएगा

संबंधत नधाु रतीके साथ यायनणु यनधकारी। Iपारकदशामयहएकमहवपणू कदमहै

स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और बढ़ावा देना और शो जारी करने की आवश्यकता को कम करना

कारण नोटिस।

6.0 एससीएन जारी करने का अधिकार: एक एससीएन आदर्श रूप से अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए

मामले का न्यायनिर्णयन करें क्योंकि यह जवाबदेही के साथ-साथ मांगों के रूप में परीक्षा की कठोरता सुनिश्चित करता है

उच्च रैंक के अधिकारियों द्वारा अधिक मात्रा में निर्णय लिया जाता है। प्राधिकरण का विवरण

शुल्क की मांग के अनुसार मामलों का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार अनुच्छेद संख्या में चर्चा की गई है। 1 1।

हालांकि, मामले का न्यायनिर्णयन करने के लिए अधिकृत रैंक के एक अधिकारी द्वारा एससीएन जारी करना है

स्वीकृत मानदंड, एक के अलावा अन्य रैंक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा जारी एक एससीएन

परिपत्र में निर्धारित वास्तव में अवैध एससीएन नहीं होगा।

7.0 अन्यायपूर्ण संवर्धन का मुद्दा एससीएन में ही उठाया जाएगा: परिणामी वापसी के मामले में

भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क के लिए, आवेदक को ऐसे दावों की वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा कि पाया जाता है

अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप। अन्यायपूर्ण संवर्धन का प्रश्न

अपीलीय आदेश में शामिल नहीं होने पर स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकती है। जहां एक वापसी

आवेदन प्रथम दृष्टया ऐसी परीक्षा के बाद अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी पाया जाता है, एक नोटिस

आवेदक को यह बताते हुए तामील किया जाना चाहिए कि जिस आधार पर धनवापसी आवेदन दायी है

खारिज किया जाना। ऐसे मामलों में जहां धनवापसी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य है लेकिन भुगतान के लिए उत्तरदायी है

अन्यायपूर्ण संवर्धन के आधार पर उपभोक्ता कल्याण कोष, निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

निर्णय से प्रभावित है और इसलिए, आवेदक को किसी से पहले एक नोटिस तामील किया जाना चाहिए

ऐसा निर्णय लिया जाता है।

8. आकलन के लंबे समय से चले आ रहे अभ्यास को बदलना: का एक दीर्घकालीन अभ्यास

मूल्यांकन जो पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचलित है, को अचानक से नहीं बदला जाना चाहिए

ड्यूटी की मांग को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करना। इस तरह के मुद्दों को बोर्ड को भेजा जाना चाहिए:

प्रस्तावित के संबंध में अन्य क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट के साथ व्यापक तरीके से

मूल्यांकन के अभ्यास में परिवर्तन। शुल्क की मांग यदि कोई हो तो सामान्य तक सीमित होनी चाहिए

ऐसे मामलों में अवधि के रूप में ऐसे मामलों में मूल्यांकन का अभ्यास दोनों व्यापार के लिए भी जाना जाता है
विभाग के रूप में।

9.1 एससीएन की छूट: एससीएन की छूट के मुद्दे को जारी परिपत्र में निपटाया गया है
एफ.सं. 137/46/2015-सेवा कर दिनांक 18.08.2015। दिए गए स्पष्टीकरण का सार यह है कि
निर्धारिती के लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर लिखित एससीएन की आवश्यकता को माफ किया जा सकता है
और शुल्क देय शुल्क के साथ मौखिक रूप से समझाया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण दिया गया
शुल्क, ब्याज और जुर्माने के भुगतान पर मामलों को बंद करने के संदर्भ में। हालांकि, जहां
इस मुद्दे पर निर्धारिती द्वारा बाद की तारीख में मुकदमा चलाने की संभावना है, यह उचित होगा कि a
लिखित एससीएन जारी किया जाए। यह विशेष रूप से गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए सही होगा या
जहां कर्तव्य उच्च में शामिल है। कार्यवाही के निष्कर्ष को एक अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है
ऐसे मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रैंक के बराबर। मामले हो सकते हैं
डीजीसीईआई/कार्यकारी आयुक्तालय/लेखापरीक्षा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बंद
आयुक्तालय, जैसा भी मामला हो। अगर कई मुद्दों में अलग-अलग मौद्रिक मूल्य शामिल हैं
एक ही कार्यवाही से उत्पन्न होता है, तो कुल योग से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों में शामिल है
कार्यवाही के समापन के लिए उसी कार्यवाही पर विचार किया जाना चाहिए।

9.2 कार्यवाही के निष्कर्ष को निर्धारिती को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।
अधिनिर्णय आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है
कार्यवाही के इस तरह के निष्कर्ष के।

9.3 कॉल-बुक मामले: मामलों की एक कॉल बुक ऐसे मामलों में रखी जाती है जो नहीं हो सकते हैं
कतिपय विशिष्ट कारणों से तत्काल न्यायनिर्णयन किया जाता है और अधिनिर्णय को इसमें रखा जाता है
ठहराव। निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को कॉल बुक में स्थानांतरित किया जा सकता है: -

मैं। ऐसे मामले जिनमें विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारी के पास अपील की है।
ii. ऐसे मामले जहां उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीगेट आदि द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है।
iii. ऐसे मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से इसे लंबित रखने और रखने का आदेश दिया है
कॉल बुक में प्रवेश किया।
iv. निपटान आयोग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों को कॉल-बुक में स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे
यह पहले से ही उपरोक्त श्रेणी (ii) के अंतर्गत शामिल है। जहां कई नोटिस हैं, वहां
मामले को केवल उन नोटिसों के संबंध में स्थानांतरित किया जा सकता है जिन्होंने आवेदन किया है
समझौता आयोग, और जिसका मामला निपटान द्वारा स्वीकार किया गया है
निपटान आदेश के बाद आयोग, मामलों को कॉल-बुक से बाहर कर दिया जाएगा
जारी किया गया है या जहां मामला न्यायनिर्णयन के लिए वापस कर दिया गया है।

9.4 नोटिस पाने वाले को कॉल बुक मामलों की सूचना: एक औपचारिक संचार जारी किया जाना चाहिए

नोटिसी, जहां मामला कॉल बुक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

भाग II : कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन

10. न्यायनिर्णयन: केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को धारा . के तहत शक्तियों के साथ निहित किया गया है
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की 33ए नोटिसियों को जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन करने के लिए
और अधिकारियों के प्रति जवाबदेह। वे, निर्णायक अधिकारियों के रूप में अपनी क्षमता में अर्ध के रूप में कार्य करते हैं
न्यायिक अधिकारी। इसके अलावा धारा 2(ए) के अनुसार "न्यायिक प्राधिकारी" का अर्थ किसी भी प्राधिकरण से है
इस अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय पारित करने के लिए सक्षम है, लेकिन इसमें केंद्रीय शामिल नहीं है
केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (54 .)
1963 का), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) या अपीलीय न्यायाधिकरण।

11.1 मौद्रिक सीमा: बोर्ड ने 29.09.2016 को न्यायनिर्णयन के लिए मौद्रिक सीमाओं को संशोधित किया है।
अधिनिर्णय के संबंध में संशोधित मौद्रिक सीमा और अन्य निर्देश इस प्रकार हैं:

क्रमांक नहीं।	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अफ़सर	शुल्क/कर/क्रेडिट मांग की मौद्रिक सीमाएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर
1.	अधीक्षक	दस लाख रुपये से अधिक नहीं
2.	डिप्टी / असिस्टेंट आयुक्त	दस लाख से अधिक लेकिन पचास रुपये से अधिक नहीं लाखों
3.	अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त	पचास लाख से अधिक लेकिन दो रुपये से अधिक नहीं करोड़
4.	आयुक्त	बिना सीमा के यानी दो करोड़ रुपये से अधिक के मामले

उपरोक्त मौद्रिक सीमाएं एतद्द्वारा सभी श्रेणियों के मामलों के लिए निर्धारित की गई हैं, सिवाय
निम्नलिखित:

(ए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी के तहत वापसी (छूट सहित) के मामले, जैसे
वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के तहत सेवा कर मामलों पर भी लागू किया जाएगा
उपायुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा बिना किसी धन के न्यायनिर्णय
सीमा

(बी) क्रमांक में उल्लिखित मुद्दों से संबंधित मामले। (ए) और (डी) धारा के पहले परंतुक के तहत
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के 35बी(1) का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

क्र.सं.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मौद्रिक सीमाएं
1	अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त	रुपये से अधिक। 50 लाख
2	उप/सहायक आयुक्त	10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक नहीं।
3	अधीक्षक	10 लाख रुपये से अधिक नहीं

11.2 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

कराधान, वर्गीकरण, मूल्यांकन और सीमा की विस्तारित अवधि से जुड़े मामले होंगे:
अधीक्षकों द्वारा न्यायनिर्णयन के दायरे से बाहर रखा गया। ऐसे मामले, 10 रुपये तक
लाख, का निर्णय उपायुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा भी किया जाएगा
10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक के मामलों के अलावा।

मैं। धनवापसी मामले (छूट सहित), उपायुक्त/
बिना किसी मौद्रिक सीमा के सहायक आयुक्त

ii. मामले में एक ही मुद्दे पर अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं
विभिन्न न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, एक ही मुद्दे से जुड़े कारण बताओ नोटिस
शामिल मामले को तय करने के लिए सक्षम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णय किया जाएगा
कर्तव्य की उच्चतम राशि।

11.3 जहां अंतर शुल्क/शुल्क की मांग का भुगतान बिना ब्याज के किया जाता है, ऐसे मामलों में, दिखाएँ
ब्याज और जुर्माने की वसूली की मांग करते हुए कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए। शो कॉज़ में
नोटिस, पहले से भुगतान किए गए शुल्क के संदर्भ का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

11.4 जहां तक केवल ब्याज की वसूली के लिए जारी नोटिसों के न्यायनिर्णयन के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है
कि इन मामलों को उचित अधिकारी द्वारा तय की गई मौद्रिक सीमा के आधार पर तय किया जाना चाहिए
शुल्क राशि शामिल है और ब्याज की राशि के आधार पर नहीं। इसलिए
शुल्क की राशि जिस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, उसके लिए मौद्रिक मानदंड होना चाहिए
ऐसे मामलों को तय करने के लिए प्राधिकरण का निर्णय लेना।

11.5 यदि एक ही मुद्दे पर अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं

नोटिसी (ओं) विभिन्न न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों के प्रति जवाबदेह, कारण बताओ नोटिस जिसमें शामिल हैं:
मामले को तय करने के लिए सक्षम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा एक ही मुद्दे का निर्णय किया जाएगा
शुल्क की उच्चतम राशि शामिल है।

12.1 कार्यकारी आयुक्तालय का क्षेत्राधिकार: केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी

आयुक्तालय का क्षेत्राधिकार सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित शुल्क की मांगों के लिए एक एससीएन जारी करता है
आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्धारिती या इकाइयाँ और ऐसे मामले हैं
कार्यकारी आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा निर्णय दिया गया। कार्यकारी अधिकारी
आयुक्तालय भी सामान्य के तहत लेखापरीक्षा आयुक्तालयों द्वारा जारी एससीएन का न्यायनिर्णयन करता है
परिस्थितियां।

12.2 लेखापरीक्षा आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा निर्णय: सभी के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी
लेखापरीक्षा आयुक्तालय में रैंकों के पास कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन करने का भी अधिकार होगा
उन क्षेत्रों में जहां लंबित स्थिति लेखापरीक्षा आयुक्तालयों द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है
अधिकारी। मामलों को वितरित करने के लिए मुख्य आयुक्तों को शक्ति प्रदान की गई है
लेखापरीक्षा के विभिन्न रैंकों के अधिकारियों सहित क्षेत्र के भीतर न्यायनिर्णय
आयुक्तालय। सेवा कर क्षेत्रों के मामले में, मामलों को स्थानांतरित करना होगा
जोनों के पार। जोनल प्रभारी प्रभारी लम्बित मामलों का जायजा लेंगे
आयुक्त स्तर पर, और बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन मामलों को निर्धारित करें
आयुक्त (लेखापरीक्षा) और सभी क्षेत्रों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यदि आवश्यक हो तो
ऐसा करने के लिए। के अधिकारियों द्वारा निर्णय किए गए मामलों के लिए भी समीक्षा, अपील आदि का कार्य
लेखापरीक्षा आयुक्तालय अधिनिर्णय के रूप में कार्यकारी आयुक्तालय के साथ जारी रहेगा
लेखापरीक्षा आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा एक नियम के बजाय एक अपवाद जारी रहेगा।

12.3 डीजीसीईआई द्वारा जांच किए गए मामले: डीजीसीईआई जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करता है
जो या तो एडीजी (निर्णय) या कार्यकारी आयुक्त के प्रति जवाबदेह हो सकता है
मामला हो सकता है। बोर्ड ने बुक किए गए मामलों के न्यायनिर्णयन के संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं
डीजीसीईआई द्वारा परिपत्र संख्या 994/01/2015-सीएक्स दिनांक 10.02.2015 और परिपत्र संख्या।
1000/7/2015-सीएक्स दिनांक 3 मार्च, 2015। दिए गए निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
अनुसरण करता है।

12.4 अतिरिक्त महानिदेशक के बीच न्यायनिर्णयन के लिए मामले सौंपना
(अधिनिर्णय) और क्षेत्र आयुक्तों, निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है: -

(मैं) एकाधिक कमिश्नरियों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों सहित मामले,
जहां शामिल शुल्क रुपये से अधिक है। एडीजी द्वारा 5 करोड़ का फैसला सुनाया जाएगा
(निर्णय)। हालांकि मामलों की बड़ी संख्या में लंबित होने या रिक्तियों के मामले में
एडीजी (निर्णय) का पद, महानिदेशक, सीईआई अधिक की ड्यूटी वाले मामलों को सौंप सकता है
रुपये से दिशा-निर्देशों के खंड (iv) और (v) का पालन करते हुए क्षेत्र आयुक्तों को 5 करोड़।

(ii) महानिदेशक, सीईआई कारण बताओ नोटिस देते हुए सामान्य आदेश जारी कर सकते हैं
रुपये से अधिक का शुल्क शामिल है। निर्दिष्ट क्षेत्रीय इकाइयों और/या द्वारा जारी किए गए 5 करोड़
डीजीसीईआई मुख्यालय एक विशेष एडीजी (निर्णय) के लिए।

(iii) जहां एडीजी (अधिनिर्णय) शामिल मामलों में से एक में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी है
समान मुद्दे या सामान्य साक्ष्य, महानिदेशक, सीईआई ऐसे सभी मामलों को सौंप सकते हैं
एडीजी (निर्णय) ।

(iv) कार्यपालक आयुक्त द्वारा निर्णय किए जाने वाले मामले, जब संबंधित हों:
केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एक कार्यकारी आयुक्त के अधिकार क्षेत्र का न्यायनिर्णयन द्वारा किया जाएगा
केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यकारी आयुक्त ने कहा।

(वी) कार्यपालक आयुक्तों द्वारा निर्णय किए जाने वाले मामले, जब संबंधित हों
कई आयुक्तालयों का अधिकार क्षेत्र, आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा:
जिसका अधिकार क्षेत्र, नोटिस प्राप्त करने वाला, जिससे कर्तव्य की उच्चतम मांग की गई है, गिर जाता है।
इन मामलों में, महानिदेशक, सीईआई द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया जाएगा:
बोर्ड, उद्देश्यों के लिए कार्यकारी आयुक्त को उपयुक्त क्षेत्राधिकार सौंपता है
पहचाने गए मामले के निर्णय के संबंध में।

(vi) 1 मार्च, 2015 से पहले जारी कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन जारी रहेगा
आयुक्त द्वारा जिसके समक्ष न्यायनिर्णयन कार्यवाही जारी है जब तक कि
महानिदेशक, सीईआई निम्नलिखित के संदर्भ में एक नया न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियुक्त करने के आदेश जारी करता है
ऊपर दिशानिर्देश या जहां बोर्ड के आधार पर एक नया न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियुक्त करता है
डीजीसीईआई का प्रस्ताव

(vii) जहां डीजीसीईआई एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव करता है जो अनुरूप नहीं है
उपरोक्त दिशानिर्देशों के साथ, डीजीसीईआई ऐसे प्रस्ताव को बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

(viii) आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारियों द्वारा निर्णय किए जाने वाले मामले हो सकते हैं
कार्यकारी आयुक्तालयों और उपरोक्त में केवल क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया
दिशानिर्देश आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

12.5 उपरोक्त दिशा-निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित बुक किए गए सेवा कर मामलों पर भी लागू होंगे
डीजीसीईआई द्वारा अधिसूचना संख्या 2/15-सेवा कर, दिनांक 10-2-2015 को उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया है
प्रधान आयुक्तों और आयुक्तों पर महानिदेशक, सीईआई को आवश्यक अधिकार क्षेत्र
इस संबंध में सेवा कर के.

13.0 कारण बताओ नोटिस की सेवा और दस्तावेजों पर भरोसा: एक कारण बताओ नोटिस और
कारण बताओ नोटिस में भरोसा किए गए दस्तावेजों को निर्धारिती पर तामील करने की आवश्यकता है:
न्यायनिर्णयन कार्यवाही की शुरूआत। दस्तावेज़/अभिलेख जिन पर भरोसा नहीं किया जाता है
कारण बताओ नोटिस में व्यक्तियों को उचित रसीद के तहत वापस करने की आवश्यकता है
जिन्हें जब्त कर लिया गया है। कारण बताओ नोटिस में स्वयं एक खंड शामिल हो सकता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है
संबंधित व्यक्तियों द्वारा शो की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर रिकॉर्ड एकत्र किए जा सकते हैं
कारण सूचना। आश्रित को लौटाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी का पद एवं पता
कारण बताओ नोटिस में भी अभिलेखों का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि
दस्तावेजों पर भरोसा न करने के कारण न्यायनिर्णयन की कार्यवाही में देरी नहीं होती है।

14.1 मामलों का निपटारा: बोर्ड के निर्देश के अनुसार प्रत्येक कारण बताओ नोटिस होना चाहिए
अग्रेषित, एक पत्र के साथ जिसमें कहा गया है कि पक्षकार मामले के निपटारे के लिए संपर्क कर सकता है
निपटान आयोग। जहां नोटिस प्राप्तकर्ता समझौता आयोग से संपर्क करता है, वहां
मामले को निपटान द्वारा तय किए जाने तक मामले को कॉल बुक में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है
आयोग। मामले में निपटान द्वारा निपटान के लिए अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है
आयोग, कारण बताओ नोटिस को सामान्य तरीके से तय किया जाना चाहिए, यदि
सेटलमेंट कमीशन ने मामले को सुलझाया, कॉल से हटकर कारण बताओ नोटिस
पुस्तक और निपटान के रूप में दिखाया गया है।

14.2 लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करना: कारण बताओ नोटिस आम तौर पर की समय सीमा प्रदान करता है
लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तीस दिन, हालांकि समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है
निर्धारिती के लिखित अनुरोध पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी। जहां निर्धारिती प्रस्तुत करने में विफल रहता है
लिखित उत्तर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नोटिसी को प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी कर सकता है
एससीएन का जवाब।

14.3 व्यक्तिगत सुनवाई: नोटिस प्राप्त करने वाले को जवाब देने के लिए उचित अवसर देने के बाद
कारण बताओ नोटिस, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए एक तारीख और समय तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है
मामले में व्यक्तिगत सुनवाई और निर्धारिती से व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने का अनुरोध करता है
स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई। कम से कम तीन अवसर
व्यक्तिगत सुनवाई समय के पर्याप्त अंतराल के साथ दी जानी चाहिए ताकि नोटिस लेने वाला लाभ उठा सके
सुनवाई का अवसर। प्रत्येक के लिए नोटिसी को अलग-अलग संचार किया जाना चाहिए
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर वास्तव में प्रत्येक सुनवाई/विस्तार के लिए अलग पत्र होना चाहिए
पर्याप्त अंतराल पर जारी किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो
कार्यवाही का कोई भी चरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सुनवाई स्थगित कर देता है। हालांकि,
ऐसा कोई स्थगन नोटिस प्राप्त करने वाले को तीन बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

14.4 व्यक्तिगत सुनवाई का रिकॉर्ड: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को का रिकॉर्ड रखना चाहिए
व्यक्तिगत सुनवाई और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई लिखित प्रस्तुति। इसके सबूत
निर्णय करते समय व्यक्तिगत सुनवाई और रिकॉर्ड पर लिखित प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है
मामला।

14.5 अधिनिर्णय आदेश: अधिनिर्णय आदेश एक बोलचाल का आदेश होना चाहिए। एक बोलना
आदेश एक आदेश है जो अपने लिए बोलता है। एक अच्छे न्यायनिर्णयन आदेश के परीक्षण में खड़े होने की उम्मीद है
उच्च अपीलीय मंचों पर वैधता, निष्पक्षता और तर्क। इस तरह के आदेश में सभी शामिल होना चाहिए
मुद्दे का विवरण, स्पष्ट निष्कर्ष और एक तर्कपूर्ण आदेश।
14.6 मुद्दों का विश्लेषण: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से सभी साक्ष्यों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है,
मुद्दों और रिकॉर्ड पर सामग्री, शो में कथित आरोपों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करें
कारण नोटिस। उनसे एससीएन के जवाब में उठाए गए प्रत्येक बिंदु की जांच करने की भी उम्मीद की जाती है
और उन्हें ठोस तर्क के साथ स्वीकार या अस्वीकार करें। तथ्यों और कानून के उचित विश्लेषण के बाद,
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्णय में अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को दर्ज करे
गण।
14.7 आदेश का मुख्य भाग: न्यायनिर्णयन आदेश में सामान्यत: निम्नलिखित के संक्षिप्त तथ्य होने चाहिए
पक्ष द्वारा मामला, लिखित और मौखिक प्रस्तुतियाँ, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का अवलोकन
रिकॉर्ड पर साक्ष्य और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान चूक और कमीशन के तथ्य और
अंत में ऑपरेटिंग ऑर्डर। किसी भी कीमत पर, निष्कर्ष और चर्चा आगे नहीं बढ़नी चाहिए
कारण बताओ नोटिस का दायरा और आधार।
14.8 मांग की मात्रा: मांग की गई और पुष्टि की गई शुल्क स्पष्ट रूप से होनी चाहिए
परिमाणित और आदेश भाग में कानून के प्रावधान शामिल होने चाहिए जिसके तहत कर्तव्य है
पुष्टि की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। एक न्यायनिर्णयन आदेश में मांग की गई ड्यूटी नहीं हो सकती
कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित राशि से अधिक।
14.9 पुष्टिकारक साक्ष्य और जिरह: जहां एक बयान पर भरोसा किया जाता है
अधिनिर्णय की कार्यवाही, इसे स्थापित करने की आवश्यकता होगी, हालांकि प्रक्रिया
जिरह, यदि नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से जिरह के लिए अनुरोध करता है जिसका
एससीएन में बयान पर भरोसा किया जाता है। जांच के दौरान, एक बयान को पुष्ट किया जा सकता है
पुष्टिकारक साक्ष्य का संग्रह ताकि पुष्टिकारक साक्ष्य मामले का समर्थन करें
विभाग, ऐसे मामलों में जहां जिरह संभव नहीं है या बयान वापस ले लिया गया है
न्यायिक कार्यवाही के दौरान। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वापस लेने वाले बयान पर भी भरोसा किया जा सकता है
दी गई परिस्थितियों में। जिरह के लिए तुच्छ अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए
जैसे CERA के अधिकारियों से जिरह करने का अनुरोध।
14.10 आदेश जारी करना और संप्रेषित करना: उन सभी मामलों में जहां व्यक्तिगत सुनवाई की गई है
निष्कर्ष निकाला है, निर्णय को यथासंभव शीघ्रता से संप्रेषित करना आवश्यक है लेकिन नहीं

किसी भी मामले में एक महीने के बाद, असाधारण परिस्थितियों में दर्ज होने को छोड़कर फ़ाइल। आदेश के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारिती को सूचित करने की आवश्यकता है: सीईए, 1944 की धारा 37सी।

15. एक न्यायनिर्णयन आदेश के लिए शुद्धिपत्र: एक न्यायनिर्णयन आदेश का शुद्धिपत्र के वल यायनण्णा यकर्िधकारीराहीजारीकयाजाएगान ककसीअधीन र्िधकारीरा विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सही करने के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है छोटी लिपिकीय गलतियाँ जो प्रतिनिर्णय आदेश में परिवर्तन नहीं करती हैं। इसलिए, न्यायनिर्णयन आदेश सामान्य रूप से जारी किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक जारी करने के बाद न्यायनिर्णयन आदेश, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कार्यकारी अधिकारी बन जाता है, जिसका अर्थ है कि उसका जनादेश समाप्त हो जाता है क्योंकि उसने मामले के निर्णय का कार्य पूरा कर लिया है। के तौर पर अवधारणा, functus officio res judicata के सिद्धांत से बंधा है , जो पुन: को रोकता है एक ही न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष किसी मामले को खोलना। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है और अधिनिर्णय आदेश में संशोधन करना।

16. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का स्थानांतरण: न्यायनिर्णायक अधिकारियों से आदेश जारी करने की अपेक्षा की जाती है मूल रूप से उन मामलों में कार्यमुक्त होने से पहले जहां व्यक्तिगत सुनवाई पूरी हो चुकी है। कार्यालय में उत्तराधिकारी द्वारा आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकता पूर्वज। कार्यालय में उत्तराधिकारी को पहले नोटिस देने वाले को नए सिरे से सुनवाई की पेशकश करनी चाहिए मामले का निर्णय करना और न्यायनिर्णयन आदेश/औपचारिक आदेश जारी करना।

16.1 आदेश पर हस्ताक्षर: निर्णायक आदेश पर न्यायनिर्णायक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए केवल अधिकार और इसे आगे किसी अन्य अधिकारी और न्यायनिर्णायक को नहीं सौंपा जाना चाहिए नोटिसी(ओं) को दिया गया आदेश मूल रूप से हस्ताक्षरित प्रति होना चाहिए न कि सत्यापित प्रति।

17.1 सीईआरए द्वारा उठाए गए एसओएफ/एलएआर का न्यायनिर्णयन जो डीएपी में परिवर्तित नहीं होते हैं: एसओएफ/एलएआर का जवाब कमिश्नरी द्वारा दिया जाता है और इसलिए इन मामलों का न्यायनिर्णयन किया जा सकता है यह सुनिश्चित करने के बाद कि कमिश्नरी द्वारा दिया गया उत्तर रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

17.2 स्वीकृत डीएपी/एपी का न्यायनिर्णयन: डीएपी का जवाब मंत्रालय (सीबीईसी) द्वारा दिया जाता है और इसलिए डीएपी का न्यायनिर्णयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया जाना चाहिए कि द्वारा दिया गया उत्तर मंत्रालय (सीबीईसी) रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

17.3 न्यायनिर्णायक प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है और कानूनी रूप से न्यायनिर्णयन करने के लिए बाध्य है स्वतंत्र रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखते हुए मामला सीईआरए/सीआरए, ऊपर बताए अनुसार विभाग का जवाब, पार्टी का जवाब, प्रासंगिक कानूनी

प्रावधान, विषय पर मामला कानून और बोर्ड के प्रासंगिक परिपत्र, यदि कोई हो। इस सम्बन्ध में
सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम के मामले में फैसले से निम्नलिखित उद्धरण
माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के सेवा कर आयुक्त दिनांक 07.04.2016 पैरा 74
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय अक्षरशः पालन किया जा सकता है

यह अच्छी तरह से तय है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए न कि उसके निर्देशों पर
कुछ अन्य प्राधिकरण। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयुक्त ने विवादित शो जारी किया
बिना किसी स्वतंत्र विचार के सीईआरए के कहने पर कारण नोटिस, और
इस प्रकार, अपनी शक्तियों और कर्तव्य का त्याग कर दिया, जो कानून में अनुमेय नहीं है।

तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि सीईआरए द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए
जांच की और जहां आवश्यक हो, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि
एससीएन सीईआरए/सीआरए की प्राप्ति पर किए गए स्वतंत्र परीक्षण का परिणाम है
आपत्ति। ऐसे स्वतंत्र निष्कर्षों को कारण बताओ नोटिस में भी शामिल किया जाना चाहिए
जैसा कि न्यायनिर्णयन आदेश में है।

17.4 जहां कोई मुद्दा लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन था और बाद में या तो न्यायिक रूप से किया गया है
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा या जहां बोर्ड का एक परिपत्र किया गया है, बसा हुआ है
इस विषय पर जारी, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर बोर्ड के साथ आगे पत्राचार, भले ही
वे डीएपी बन गए हैं, आवश्यक नहीं है और ऐसे मामलों का निर्णय गुणदोष के आधार पर किया जा सकता है
नवीनतम निर्णयों और परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए।

भाग III: पुष्टि की गई मांगें/वसूली

18. पुष्ट मांगें: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जो
शुल्क और केंद्र को देय किसी भी प्रकार की अन्य राशि की वसूली के लिए प्रयोग किया जा सकता है
सरकार। यह ध्यान दिया जा सकता है कि शुल्क और अन्य राशियों को देय माना जाता है
निम्नलिखित स्थितियों में सरकार:

(i) जहां निर्णय या अपील में पुष्टि आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है और
अपील की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है;

(ii) जहां सीईएसटीएटी या उच्च न्यायालय ने मांग की पुष्टि की है और कोई स्टे लागू नहीं है
जैसा कि पैरा 23.2 में बताया गया है।

(iii) जहां पैरा . में स्पष्ट किए गए अनुसार आवधिक विवरणी में एक स्वीकृत देयता परिलक्षित होती है
24.

19. वसूली की शक्तियां: पुष्टि की गई मांग की वसूली इनमें से किसी एक का प्रयोग करके की जा सकती है
सीईए, 1944 की धारा 11 के तहत शक्तियां जैसे देय रिफंड से समायोजन,
ऐसे व्यक्ति के उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की और बिक्री या प्रमाणपत्र कार्रवाई के माध्यम से इलाज
भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि। लेने का विकल्प समाप्त करने के बाद
उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाती है, यदि देय राशि की वसूली नहीं होती है, तो के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 जिसे समान मामलों पर लागू किया गया है:
केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसके अलावा, जहां पूरे कारोबार को संपत्ति और देनदारियों के साथ निपटाया जाता है,
व्यवसाय में भी उत्तराधिकारी से शुल्क या कोई अन्य राशि वसूल की जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है
कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत, अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क
अधिकारियों को किसी अन्य व्यक्ति को आदेश जारी करने का अधिकार है, जिससे पैसा देय है
ऐसा व्यक्ति जिससे बकाया की वसूली अपेक्षित है। वसूली के लिए ऐसा नोटिस
अन्य व्यक्ति को आम तौर पर गार्निशी नोटिस के रूप में संदर्भित किया जाता है।

20. परिसमापन के तहत संपत्ति से वसूली: दिवाला की धारा 53 और
दिवालियापन संहिता, 2016 से प्राप्त आय के वितरण के लिए प्राथमिकता के क्रम का प्रावधान है
परिसमापन संपत्ति की बिक्री। की धारा 11ई में पैरा-मटेरिया परिवर्तन किए गए हैं
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बकाया, यदि कोई हो, बैंक को देय ऋण की वसूली और
वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और
सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का प्रवर्तन
बरामद किए गए हैं।

20.1 बीआईएफआर/आईएफसीएल/ओएल/डीआरटी/दिवालियापन से पहले लम्बित रहने के दौरान वसूली और
दिवालियापन संहिता, 2016: जब मामले बीआईएफआर/आईएफसीएल/ओएल/उपयुक्त के समक्ष लंबित हों
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत प्राधिकरण तो ऐसे मामलों में वसूली के उपाय
सहारा नहीं लेना चाहिए। ऐसे मामलों में लोक अधिवक्ताओं को हलफनामा दाखिल करने की सलाह दी जानी चाहिए:
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ई के तहत प्रथम प्रभार की मात्रा को सूचित करते हुए
बीआईएफआर / आईएफसीएल / ओएल / डीआरटी / दिवाला और दिवालियापन संहिता प्राधिकरणों को पुष्टि की मांग।

20.2 मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वसूली: बोर्ड ने इस विषय पर दो परिपत्र जारी किए हैं
परिपत्र संख्या 984/08/2014-सीएक्स दिनांक 16.9.2014 और परिपत्र संख्या 1035/23/2016-सीएक्स दिनांक
4.7.2016।

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35F की उप-धारा (iii) और की धारा 129E
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसरण में देय शुल्क या दंड के 10% के भुगतान को निर्धारित करता है
निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है अर्थात आयुक्त (अपील) का आदेश। में
ट्रिब्यूनल के समक्ष आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ अपील की स्थिति, 10% है

मांग की गई शुल्क की राशि या आयुक्त (अपील) द्वारा लगाए गए दंड पर भुगतान किया जाएगा।
यह आवश्यक नहीं है कि मांग की गई शुल्क की राशि या आदेश में लगाए गए दंड के समान हो
उक्त मामले में मूल.

(ii) ऐसे मामले में, जहां अकेले दंड विवाद में है और दंड के तहत जुर्माना लगाया गया है
अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, पूर्व-जमा की गणना के योग के आधार पर की जाएगी
जिस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का प्रस्ताव है, उस आदेश में लगाए गए सभी दंड।

(iii) धारा के तहत निर्धारित राशि के किसी भी कम भुगतान या गैर-भुगतान के मामले में
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की 35F या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129E, अपील
दायर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

(iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ को 6.8.14 से 6.8.14 तक संशोधित किया गया है
जहां ड्यूटी . की मांग की गई ड्यूटी के 7.5% या 10% के अनिवार्य भुगतान का प्रावधान करें
मांग विवाद में है या जहां मांग की गई शुल्क और लगाया गया जुर्माना विवाद में है
आयुक्त (अपील) या सीईएसटीएटी के समक्ष अपील की स्वीकृति। एक बार राशि का भुगतान करने के बाद,
लंबित रहने के दौरान बकाया राशि की वसूली के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी
इन अधिकारियों के समक्ष अपील की कार्यवाही।

20.3 उन मामलों में जहां स्थगन आवेदन आयुक्त (अपील) या सेस्टेट के समक्ष लंबित है
6-8-2014 से पहले की अवधि के लिए, ठहरने के लंबित रहने के दौरान कोई वसूली नहीं की जाएगी
आवेदन पत्र।

20.4 सीईएसटीएटी या उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मांग की वसूली: जहां मांग की गई है
CESTAT या उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, वसूली कार्यवाही शुरू की जा सकती है
आदेश जारी होने के साठ दिन, बशर्ते उच्च न्यायालय या सर्वोच्च द्वारा कोई रोक न दी गई हो
कोर्ट जैसा भी मामला हो।

21. आवधिक विवरणियों में स्वीकृत देयता की वसूली: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का नियम 8(4)
नियम, 2002 में प्रावधान है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के प्रावधान
आवधिक रिटर्न में देय घोषित राशि की वसूली के लिए आवेदन करें लेकिन भुगतान नहीं किया गया। धारा 11
जैसा कि ऊपर पैरा 21 में बताया गया है, बकाया की वसूली के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
दूसरी ओर धारा 11ए(16) में प्रावधान है कि धारा 11ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे
शुल्क कम भुगतान किया गया या भुगतान नहीं किया गया जो कि स्व-मूल्यांकन किया गया है और आवधिक रिटर्न में घोषित किया गया है।
इन दो प्रावधानों के संयुक्त पठन से पता चलता है कि जहां कर्तव्य की देयता स्वीकार की जाती है
लेकिन निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किया गया, धारा 11ए के तहत परिकल्पित न्यायनिर्णयन कार्यवाही नहीं है
किये जाने की आवश्यकता है। इस तरह की स्व-स्वीकृत देयता अभिव्यक्ति के तहत कवर की जाएगी

Machine Translated by Google

केंद्र सरकार को देय शुल्क और किसी भी प्रकार की कोई अन्य राशि जो धारा 11ए में उपयोग की जाती है स्वीकृत दायित्व की वसूली के लिए नोटिस धारा 11 और के तहत निर्धारिती पर तामील किया जा सकता है जब इस तरह के बकाया का भुगतान उचित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

22.0 किश्तों में वसूली: बोर्ड ने परिपत्र संख्या 996/3/2015-सीएक्स दिनांक 28 तारीख जारी किया है किश्तों में पुष्टि की गई मांग के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए फरवरी, 2015।

22.1 बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बकाया करों, ब्याज और . की वसूली की अनुमति दी जाए किश्तों में जुर्माना। मासिक किश्तों में इस तरह के भुगतान की अनुमति देने की शक्ति होगी विवेकाधीन और आयुक्तों द्वारा भुगतान की मंजूरी देने के लिए प्रयोग किया जाएगा किश्तों में बकाया अधिकतम 24 मासिक किश्तों तक एवं मुखिया द्वारा 24 . से अधिक मासिक किश्तों में बकाया भुगतान की स्वीकृति के लिए आयुक्त और अधिकतम 36 मासिक किश्तों तक।

22.2 किश्तों में बकाया भुगतान करने की सुविधा सामान्यतः कंपनियों को दी जाएगी जो कंपनी जैसे किश्तों में बकाया भुगतान के लिए एक उचित कारण दिखाते हैं अस्थायी वित्तीय संकट में होना। किश्तों में भुगतान की स्वीकृति एवं की संख्या किश्तें इस तरह तय की जानी चाहिए कि बकाया की वसूली और की समग्र वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखा जाता है कंपनी, उसकी संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय। बार-बार चूककर्ता नहीं हो सकते हैं किश्तों में बकाया भुगतान की अनुमति। निर्णय मामले के आधार पर लिया जाएगा मामले के तळ्ठयराजक्व के हतके ⓔ करकॉड्ड कोयानमरखते ॥ए कंपनी, उसकी वित्तीय स्थिति, आदि।

22.3 बकाया के भुगतान की अनुमति के लिए आवेदन क्षेत्राधिकार में किया जाएगा आयुक्त ने इसका पूरा औचित्य बताया। आवेदन की स्वीकृति चाहिए लिखित में उचित पावती के साथ रिकॉर्ड में लिया जाए। अनुमति स्पष्ट रूप से होनी चाहिए किश्तों की संख्या और उस महीने की पहचान करें जिससे किश्तों का भुगतान किया गया है शुरू करना चाहिए और यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए कि के भुगतान में चूक के मामले में किश्तों में, अनुमति वापस ले ली जाएगी और की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी बकाया

22.4 इस प्रयोजन के लिए आयुक्त अनुमति को रद्द करने की शक्ति का भी प्रयोग करेंगे किश्तों में बकाया भुगतान करने के लिए। में चूक के मामलों में रद्द करने का सहारा लिया जाना चाहिए किश्तों का भुगतान या जब कंपनी वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो रही हो और वहाँ है

Machine Translated by Google

व्यापार के बंद होने की संभावना। किश्तों में भुगतान की अनुमति रद्द करने के बाद,
बकाया की वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

भाग IV: विविध

23: निर्णयों की तामील, आदेश, सम्मन, आदि: की सेवा के लिए वैधानिक प्रावधान
सीईए, 1944 की धारा 37सी के तहत निर्णय, आदेश, सम्मन आदि प्रदान किए गए हैं।
यह अनुभाग प्रदान करता है कि किसी भी आदेश या नोटिस की अन्य बातों के साथ सेवा, जिसमें शामिल होगा
सेवा के लिए एक एससीएन या एक न्यायनिर्णयन आदेश को निर्धारित तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है
पूर्ण माना जाए। अनुभाग सेवा के विभिन्न तरीकों का प्रावधान करता है जैसे कि by
देय पावती के साथ या कमबैक के रूप में पंजीकृत डाक द्वारा निविदा देना या भेजना
कारखाने या गोदाम या अन्य स्थान के किसी विशिष्ट भाग पर उसकी एक प्रति चिपका कर
व्यवसाय या व्यक्ति के निवास का सामान्य स्थान या आगे की वापसी के रूप में, पर चिपका कर
अधिकारी का नोटिस बोर्ड। अधिक जानकारी के लिए, अनुभाग को संदर्भित किया जा सकता है।

24. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रिमांडेड डे नोवो या एडज्यूडिकेशन: डे नोवो के मामलों में
अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण में निर्णय, ऐसे मामलों का निर्णय किया जाना चाहिए
उसी रैंक के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश पारित किया था जो अपील में था
अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, न्यायनिर्णयन की शक्ति में वृद्धि के बावजूद
अधिकारियों की। अपीलीय प्राधिकारी से नए सिरे से अधिनिर्णय का आदेश प्राप्त होने पर,
ऐसे मामले को लंबित न्यायनिर्णयन के मामलों की सूची में लंबित के रूप में दिखाया जाना चाहिए
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी जब तक यह उसके द्वारा तय नहीं किया जाता है। ऐसे लंबित डी-नोवो की कड़ी निगरानी
मामलों को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि इन मामलों को समय सीमा के भीतर अच्छी तरह से निपटाया जाता है, यदि
अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई भी।

25. स्वैच्छिक भुगतान पर कोई एससीएन नहीं: कम भुगतान या कर का भुगतान न करने की किसी भी स्थिति में/
ऐसे मामले में कर्तव्य जिसमें विस्तारित अवधि शामिल नहीं है, एक व्यक्ति जिसने देय शुल्क का भुगतान किया है
ब्याज के साथ, यदि कोई हो, स्वयं कर्तव्य का पता लगाकर, या जैसा कि केंद्र द्वारा सुनिश्चित किया गया हो
आबकारी अधिकारी को इस प्रकार भुगतान किए गए शुल्क या किसी दंड के संबंध में कोई नोटिस तामील नहीं किया जाएगा।
धारा 11ए(1)(बी) के साथ पठित धारा 11ए(2) के प्रावधानों को इसमें संदर्भित किया जा सकता है
संबद्ध।

26. पूर्व-जमा की वापसी:- (i) जहां अपील का निर्णय के पक्ष में किया जाता है
पार्टी / निर्धारिती, वह ब्याज के साथ जमा की गई राशि की वापसी का हकदार होगा:
जमा करने की तिथि से वापसी की तिथि तक निर्धारित दर

Machine Translated by Google

(ii) अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा शुल्क का भुगतान नहीं है। इसलिए, पूर्व-जमा की वापसी की आवश्यकता केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बी के तहत शुल्क की वापसी की प्रक्रिया के अधीन नहीं होगा, 1944. इसलिए, सभी मामलों में जहां अपीलीय प्राधिकारी ने मामले का फैसला के पक्ष में किया है अपीलकर्ता को, ब्याज सहित वापसी का भुगतान अपीलकर्ता को 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए वापसी की मांग करने वाले अपीलकर्ता के पत्र की प्राप्ति, चाहे वह आदेश का हो या नहीं अपीलीय प्राधिकारी को विभाग द्वारा चुनौती दी जानी प्रस्तावित है या नहीं।

(iii) यदि विभाग आयुक्त (ए) के आदेश के खिलाफ अपील करने पर विचार करता है या सीईएसटीएटी का आदेश, जो अपीलकर्ता के पक्ष में है, ब्याज के साथ वापसी अभी भी जारी रहेगी कानून या आदेश में निर्धारित समय सीमा के अनुसार देय हो, जब तक कि ऐसा आदेश न हो सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रोक दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में परिणामी वापसी, आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के अलावा, यह भी आवश्यक है कि a वापसी की गई राशि की सुरक्षात्मक मांग धारा 11ए के तहत कम से कम नहीं जारी की जाए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक/उपायुक्त के लिए नई मौद्रिक सीमा के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा मामलों का न्यायनिर्णयन और कॉल-बुक में स्थानांतरित।

(iv) रिमांड की स्थिति में, पूर्व-जमा की वापसी ब्याज सहित देय होगी।

Machine Translated by Google

अनुबंध-मैं

रद्द किए गए परिपत्रों/निर्देशों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र / निर्देश
1	32/80-सीएक्स.6 दिनांक 26.7.80
2	5/83-सीएक्स.6 दिनांक 10.3.1983
3	207/47/85-सीएक्स.6, दिनांक 12.8.1986
4	17/87, दिनांक 18.3.1987
5	267/104/87, दिनांक 15.12.1987
6	27/88-सीएक्स.6, दिनांक 7.4.1988
7	42/88-सीएक्स.6, दिनांक 24.5.1988
8	48/88-सीएक्स.6, दिनांक 10.6.1988
9	50/88-सीएक्स.6, दिनांक 17.6.1988,
10	67/17/88-सीएक्स.2, दिनांक 18.8.1988
11	76/88-सीएक्स.6, दिनांक 2.11.1988
12	79/88-सीएक्स.6, दिनांक 15.11.1988
13	66/88, दिनांक 20.12.1988
14	2/89, दिनांक 9.1.1989
15	29/89, दिनांक 2.5.1989
16	50/89, दिनांक 29.8.1989
17	53/90-सीएक्स.3, दिनांक 6.9.90
18	1/90-एयू दिनांक 19.3.90
19	18/90-सीएक्स.8, दिनांक 28.3.1990 53/90, दिनांक
20	26.9.1990 21/90, दिनांक 6.12.1990
21	
22	289/10/91-सीएक्स.9 दिनांक 18.03.1991
23	3/92-सीएक्स.6
24	167/39/92-सीएक्स.4, दिनांक 13.10.1992
25	5/92, दिनांक 13.10.1992
26	20/92-सीएक्स.6, दिनांक 21.12.1992
27	13/93-सीएक्स.6 दिनांक 15.10.93
28	9/93-सीएक्स.6, दिनांक 8.7.1993
29	19/93-सीएक्स.6, दिनांक 29.12.1993
30	20/20/94-सीएक्स, दिनांक 10.2.1994
31	67/67/94-सीएक्स, दिनांक 19.10.1994
32	32/32/94-सीएक्स दिनांक 11.04.1994
33	162/73/95-सीएक्स.3, दिनांक 14.12.95
34	163/74/95-सीएक्स, दिनांक 14.12.1995
35	171/5/96-सीएक्स, दिनांक 2.2.1996
36	228/62/96-सीएक्स, दिनांक 8.7.1996
37	268/102/96-सीएक्स, दिनांक 14.11.1996
38	208/42/96-सीएक्स दिनांक 02.05.1996
39	354/118/96-टीआरयू, दिनांक 6.1.1997
40	290/6/97-सीएक्स। दिनांक 20.1.1997
41	295/11/97-सीएक्स., दिनांक 10.2.1997
42	298/14/97-सीएक्स, दिनांक 25.2.1997
43	299/15/97, दिनांक 27.2.1997

Machine Translated by Google

44	312/28/97-सीएक्स., दिनांक 22.4.1997
45	317/33/97-सीएक्स, दिनांक 18.6.197 328/44/97-सीएक्स, दिनांक
46	13.8.1997
47	350/66/97-सीएक्स। दिनांक 4.11.1997
48	362/78/97-सीएक्स, दिनांक 9.12.1997
49	385/18/98-सीएक्स दिनांक 30/3/98
50	373/06/98-सीएक्स, दिनांक 20.1.98
51	444/10/99-सीएक्स, दिनांक 12.3.1999
52	502/68/99-सीएक्स, दिनांक 16.12.1999
53	518/14/2000-सीएक्स, दिनांक 3.3.2000 523/19/2000-सीएक्स। दिनांक
54	6.4.2000 534/30/2000-सीएक्स, दिनांक 30.5.2000
55	
56	540/36/2000-सीएक्स., दिनांक 8.8.2000
57	552/48/2000-सीएक्स, दिनांक 4.10.2000
58	555/51/2000-सीएक्स, दिनांक 19.10.2000
59	588/25/2001-सीएक्स, दिनांक 19.9.2001
60	592/29/2001-सीएक्स, दिनांक 19.10.2001
61	606/43/2001-सीएक्स, दिनांक 4.12.2001
62	674/65/2002-सीएक्स दिनांक 1.11.2002
62	275/37/2के-सीएक्स.8ए दिनांक 2.1.2002
64	655/46/2002-सीएक्स दिनांक 26.6.2002
65	712/28/2003-सीएक्स., दिनांक 5-5-2003
66	718/34/2003-सीएक्स, दिनांक 23.5.2003
67	723/39/2003-सीएक्स, दिनांक 10.6.2003
68	744/60/2003-सीएक्स, दिनांक 11.9.2003 752/68/2003-सीएक्स, दिनांक
69	1.10.2003
70	762/78/2003-सीएक्स। दिनांक 11.11.2003
71	765/81/2003-सीएक्स, दिनांक 10.12.2003 766/82/2003-सीएक्स दिनांक
72	15.12.2003
73	732/48/2003-सीएक्स दिनांक 5.8.03
74	794/27/2004-सीएक्स, दिनांक 23.6.2004 806/3/2005-सीएक्स, दिनांक
75	12.1.2005
76	207/09/2006-सीएक्स.6, दिनांक 8.9.2006
77	208/27/2003-सीएक्स.6, दिनांक 18.12.2006
78	865/3/2008-सीएक्स। दिनांक 19.2.2008
79	922/12/2010-सीएक्स।, दिनांक 18.5.2010
80	957/18/2011-सीएक्स.3, दिनांक 25.10.11
81	962/05/2012-सीएक्स दिनांक 28/03/2012
82	967/1/2013-सीएक्स, दिनांक 1.1.2013
83	201/01/2014-सीएक्स.6, दिनांक 26-6-2014
84	994/01/2015-सीएक्स, दिनांक 10.02.2015
85	996/3/2015-सीएक्स, दिनांक 28.2.2015 1000/7/2015-सीएक्स, दिनांक
86	3.3.2015
87	390/सेस्टेट/69/2014-जेसी, दिनांक 22.12.2015
88	1035/23/2016-सीएक्स, दिनांक 4.7.2016
89	1049/37/2016-सीएक्स, दिनांक 29.9.2016

Machine Translated by Google

अनुबंध द्वितीय

उन परिपत्रों/निर्देशों की सूची जिन्हें रद्द नहीं किया गया है

क्र.सं.	परिपत्र / निर्देश
1	984/08/2014-सीएक्स, दिनांक 16.9.2014
2	137/46/2015-एसटी, दिनांक 18.8.2015
3	1023/11/2016-सीएक्स, दिनांक 8.04.2016